साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 21-27 अगस्त 2023 वर्ष-9, अंक-19

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

लोकसभा में केंद्र सरकार के पेश आंकड़ों से हुआ खुलासा

फसल बीमा का 70 फीसदी क्लेम मप्र-राजस्थान और महाराष्ट्र ने लिया

» मध्य प्रदेश के किसानों को 16,658 करोड़ रुपए मिला

» किसानों को तीन साल में 41 हजार करोड़ रुपए मिले

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में मौसम की सबसे ज्यादा मार तीन राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र) पर पड़ रही है। 2019-20 से 2021-22 के बीच इन तीन राज्यों ने कुल 41,824 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम लिया, जबकि इसी दौरान पूरे देश में 59,429 करोड़ का क्लेम दिया गया, यानी 70 फीसदी हिस्सेदारी इन्हीं तीन राज्यों की रही। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये आंकड़े सामने रखे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) का कहना है कि फसलें बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह है-प्रतिकूल मौसम। इस साल फरवरी महीना देश में 122 साल के इतिहास का सबसे गर्म रहा। एक साल पहले यानी 2022 की जनवरी 122 साल के इतिहास की सबसे ठंडी थी।

क्लेम लेने में मध्य प्रदेश के किसान (16,658 करोड़) पहले, राजस्थान (12,714 करोड़) दूसरे और महाराष्ट्र (12,452 करोड़ रुपए) तीसरे नंबर पर हैं। 2021-22 में फसल बीमा के लिए सबसे ज्यादा क्लेम महाराष्ट्र (4,374 करोड़ रुपए) के किसानों को दिया गया। मगर 2019-20 में महाराष्ट्र के 1,320 करोड़ रुपए के मुकाबले मध्य प्रदेश को 7,781

मध्यप्रदेश में कंपनियों ने ज्यादा भरा क्लेम

मध्यप्रदेश में 2019-20 के दौरान 78.92 लाख किसानों ने 1.12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र का 32,030 करोड़ रुपए का बीमा 3,758 करोड़ रुपए के प्रीमियम में कराया। 6,195 करोड़ रुपए क्लेम लिया। हालांकि, प्रीमियम के लिए किसानों ने सिर्फ 629 करोड़ दिए, बाकी सरकार ने भरे। 2019-20 में राजस्थान के 85 लाख किसानों ने 967 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए 34,909 करोड़ रुपए का बीमा कराया। 5,060 करोड़ रुपए प्रीमियम भरा और 4,993 करोड़ क्लेम लिया।

मप्र में प्रतिकूल मौसम: मप्र में नवंबर तक 273 दिनों में 198 दिन प्रतिकूल मौसम रहा। राजस्थान की बात करें तो 2021 में सूखे और बाढ़ दोनों की ही स्थितियां बनीं। इससे 20 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें खराब हुईं।

महाराष्ट्र में बर्बादी: 2022 में जून-सितंबर के बीच यानी पूरे बारिश के सीजन में महाराष्ट्र में 80 दिन प्रतिकूल मौसम रहा। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि 5 साल में राज्य में 7 हजार करोड़ रुपए की 3.6 करोड़ हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।

यूपी: 46 लाख किसानों ने 35 लाख हेक्टेयर फसल का 16,743 करोड़ रुपए का बीमा 1304 करोड़ प्रीमियम देकर कराया। 1,092 करोड़ रुपए का क्लेम लिया।

गुजरात: 24 लाख किसानों ने 29.43 लाख हेक्टेयर का 16,143.17 करोड़ का बीमा 3,614 करोड़ प्रीमियम देकर करवाया था, लेकिन 112 करोड़ का ही क्लेम मिला।

तेलंगाना: 10.33 लाख किसानों ने 11.34 लाख हेक्टेयर का 8,459 करोड़ का बीमा 880.75 करोड़ में कराया। कोई क्लेम नहीं मिला।

2021-22 में 16 राज्यों ने 18,043 करोड़ रुपए का क्लेम लिया

2020-21 में फसल बीमा के लिए देशभर के 5 करोड़ किसानों ने आवेदन दिया था, लेकिन 2.47 करोड़ ही योग्य पाए गए। इनमें महाराष्ट्र के 64 लाख, मप्र के 50 लाख व राजस्थान के 36 लाख थे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश के 16 राज्यों ने कुल 18,043 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम लिया। इनमें यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड आदि शामिल हैं। हालांकि, 2020-21 में इन 16 राज्यों ने 20,771 करोड़ रुपए का क्लेम हासिल किया था।

- गेहूं उत्पादन के लिहाज से मध्य भारत के इलाके अहम हैं। कुल गेहूं उत्पादन में मप्र की 21 फीसदी हिस्सेदारी है। बेमौसम बारिश, बाढ़ जैसी घटनाएं आम हैं। तापमान सामान्य से ज्यादा होता है। इससे फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा। इस साल कहीं ज्यादा और कहीं कम बारिश के कारण अब तक करीब 23.5 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है, जो जुलाई-22 के मुकाबले 487 फीसदी ज्यादा है। ऐसे में फसल बीमा बेहद जरूरी है।

किरण पांडेय, प्रोग्राम डायरेक्टर, सीएसई

20 गोदामों में भंडारित अनाज बर्बाद

जबलपुर में सड़ गया 35 करोड़ का खाद्यान्न

जबलपुर। जागत गांव हमार

जिले में रबी और खरीफ का उपार्जन भरपूर है, लेकिन खाद्यान्न के रखरखाव में लापरवाही और उनका समय पर उपयोग नहीं किए जाने की वजह से 35 करोड़ रुपए से अधिक का खाद्यान्न सड़ गया है। अब इस खाद्यान्न को नीलाम करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम (नान) और वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन (डब्ल्यूएचएलसी) तैयारी कर रहा है। नान और डब्ल्यूएचएलसी की अनुशंसाओं पर गौर करें तो जिले के करीब दो दर्जन गोदामों में रखा खाद्यान्न अखाद्य श्रेणी का हो चुका है। अनेक गोदामों में तो खाद्यान्न की स्थिति ऐसी है कि वहां के सड़े अनाज को पशु भी न खाएं। नान और डब्ल्यूएचएलसी की ओर से भोपाल को पत्र लिखा जा चुका है कि जिले के 20 से अधिक गोदामों में किसानों से खरीद कर भंडारित अनाज सड़ चुका है। डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन कमेटी की ओर से इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव के बाद भोपाल से जांच दल आएगा और नीलामी की औपचारिकताओं को पूरा करेगा।

इन क्षेत्रों में खराब हुआ खाद्यान्न

पाटन, सिहोरा और तिलसानी की गोदामों रखे अनाज के खराब होने की सूचना है। इन गोदामों में 20 हजार टन से अधिक खाद्यान्न सड़ चुका है। तिलसानी के ओपनकैप स्टोरेज में रखे 1400 टन गेहूं की नीलामी हो चुकी है। खाद्यान्न के इस स्टाक को उसकी स्थिति के आधार पर 800 से 1500 रुपए क्विंटल के भाव से नीलाम किया जा चुका है।

- जिले के विभिन्न गोदामों में करीब 20 हजार टन खाद्यान्न खराब हो चुका है। उसकी नीलामी के लिए भोपाल को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा तिलसानी कैप स्टोरेज के 1400 टन की नीलमी हो चुकी है।

-सखाराम निमोदा, जिला प्रबंधक, डब्ल्यूएचएलसी

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर बोले-खेती मजबूत अर्थव्यवस्था का अंग

प्रदेश फसल उत्पादन, बागवानी, दुग्ध और जैविक खेती में अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

भाजपा सरकार ने विकास, गरीब कल्याण, जनकल्याण के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज विकास की दृष्टि से देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक अधोसंचरना का विकास हुआ है। फिर चाहे ग्रामीण, जिला और नेशनल हाइवे की बात हो, हर जगह रोड कनेक्टिविटी है। 2003 में जब हम सरकर में आए थे तब बिजली का उत्पादन 2900 मेगावॉट होता था। ये बिजली न तो गांव में दर्शन देती थी और न ही शहर में मिलती थी, इसे मध्य प्रदेश के लोग अभी भूले नहीं है। भाजपा की सरकार ने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और आज हम बिजली की दृष्टि से सरप्लस स्टेट हैं और आज 28,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन हो रहा है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक खास चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खेती मजबूत अर्थव्यवस्था का अंग है। इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है। कृषि की दृष्टि से आज कृषि ग्रोथ रेट 18 प्रतिशत है, जो देशभर में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश फसल के उत्पादन, बागवानी, दुग्ध, जैविक, प्राकृतिक खेती में अग्रणी अवस्था में है।

65 लाख होगा सिंचाई का रकबा | केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 2003 में सिंचाई साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और अब 46 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पांच वर्षों में 65 लाख हेक्टेयार सिंचाई का रकबा किया जाएगा। गरीब के जीवन में बदलाव आए तो पीडीएस, आंगनवाड़ी, लाड़ली लक्ष्मी, संबल, लाड़ली बहना योजना, जनजातीय योजना जैसे अनेक कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से सरकार लगातार करीबों का जीवन स्तर बदलने का काम कर रही है।

दस करोड़ किसानों को मिली सम्मान निधि

तोमर ने कहा कि एक योजना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पीएम सम्मान योजना के मध्यम से हर किसान को 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष मदद मिलती है। इस योजना के अंतर्गत अभी 10 करोड़ किसानों के खातों में 2 लाख 61 हजार करोड़ जमा किया गया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम एक रुपए भेजते हैं तो गांव में जाते-जाते 15 पैसे ही बचते हैं। आज हम कह सकते हैं कि 6 हजार भेजते हैं तो पूरे 6 हजार पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे पीएम फसल योजना का एक लाख 41 हजार करोड़ मुआवजे के रूप में किसानों को देने का काम किया गया है।

जागत गांव हमार

पूरे प्रदेश में 4144 अमृत सरोवर आदर्श साबित हुए

एक समय में 146 करोड़ लीटर जल अमृत सरोवरों में होगा उपलब्ध

प्रधानमंत्री की कल्पना को साकार करता खरगोन, 146 अमृत सरोवर बनकर तैयार

खरगोन। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने की मंशा जाहिर की थी। इस मंशा का साकार स्वरूप खरगोन में पूरा किया गया है। मनरेगा परियोजना अधिकारी श्याम रघुवंशी ने बताया कि 11 अगस्त को मनरेगा आयुक्त द्वारा प्रदेश के आदर्श अमृत सरोवरों की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में खरगोन जिले के 146 अमृत सरोवर आदर्श सरोवर शामिल है। वैसे जिले में दो वर्षों में कुल 163 (151 मनरेगा से और 12 वाटरशेड से) अमृत सरोवरों पर कार्य प्रारम्भ हुआ था। इनमें से 150 पूर्ण हो चुके है। इन्ही में से 146 चुने गए हैं।

खंडवा और बुरहानपुर के एक्सपर्ट ने दी थी रिपोर्ट– मनरेगा आयुक्त भोपाल द्वारा प्रदेश में 5114 पूर्ण हुए अमृत सरोवरों की जांच कराई गई। खरगोन जाँच करने खंडवा के आरईएस कार्यपालन यंत्री सुनील बोंदणे और बुरहानपुर के शर्मा ने पानी स्टोरेज, डिजाईन, कैचमेंट एरिया, सरोवरों का चुनाव सहित कुल 25 मापदंडों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पूरे प्रदेश में 4144 अमृत सरोवर आइडियल साबित हुए है। जिसमें से 146 खरगोन जिले में स्थित है। 150 अमृत सरोवरों में 146 सरोवरों को चुना जाना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। कार्यपालन यंत्री बोंदणे से जब **जागत गांव हमार** ने पूछा कि खरगोन का सबसे अच्छा सरोवर कौन सा है जो आपको पसंद आया। उन्होंने कहा कि ऐसा बताना मुश्किल है, क्योंकि सब अपने आप में अनोखे और सुंदर हैं।

एक करोड़ लीटर का एक जल कटोरा

आरईएस के कार्यपालन यंत्री अनिल बागोले ने बताया कि भूमि का जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाब से अच्छे कोई साधन नही है। इनसें जितना जल का स्टोरेज किया जा सकता है उससे कहीं अधिक मात्रा में पानी जमीन में उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अमृत सरोवर वो युक्ति है जिससे जल स्तर निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। अमृत सरोवरों की जल ग्रहण क्षमता की बात की जाए तो 1 सरोवर में 10 हजार घन मीटर जल समा सकता है। 10 हजार घन मीटर याने की एक सरोवर में 1 करोड़ लीटर पानी तो अपने में समेट ही सकता है। जिले में ऐसे 146 आदर्श अमृत सरोवर है तो इस हिसाब से 146 करोड़ ली. अर्थात 37 हजार 878, 78 गेलन जल तो एक स्टोरेज के रूप में संरक्षित है ही।

इनका कहना है

अमृत सरोवर आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर जल नहीं है तो जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए ये सरोवर जल स्टोरेज व संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यहां समूहों को मछली पालन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

-शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, खरगोन

आने वाले समय में इन सरोवरों से मिलने वाले लाभ खुशियां देंगे। किसानों के नलकूप और कुएं बताएंगे परिणाम। इससे किसानों की फसलें लहलहाएंगी। अमृत सरोवार में खरगोन प्रदेश का मॉडल बनेगा।

-ज्योति शर्मा, सीईओ, ग्रामीण विकास विभाग

आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा सिरोल्या गांव

केवीके देवास में महिलाओं को दिया फिनायल बनाने का प्रशिक्षण

देवास। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा एसपी एमसीआईएल द्वारा प्रायोजित एवं टेरी द्वारा आयोजित एक दिवसीय स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषक महिलाओं को फिनाइल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। सिरोल्या गांव को आगामी दो वर्षों में आदर्श गांव के लिए विकसित किया जाएगा।

लाभप्रद साबित हो सकता है व्यवसाय– प्रधान वैज्ञानिक एवं केंद्र प्रमुख डॉ. एकेबडाया ने कृषक महिलाओं को कहा कि फिनाइल बनाने एवं उसका विपणन कर हम आसानी से कम लागत में अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुशलता, योग्यता, जागरूकता और विक्रय कला के गुण होना आवश्यक है। फिनाइल हमारे घरों में, अस्पतालों में, स्कूल में, होटल में तथा सभी जगह उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है। अत: इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह व्यवसाय लाभप्रद साबित हो सकता है। केंद्र की वैज्ञानिक डॉ. लक्ष्मी द्वारा स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं उसके सफल संचालन के लिए विस्तृत जानकारी दी।

गाजर घास उन्मूलन सप्ताह का आयोजन

केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा गाजर घास उन्मूलन सप्ताह का आयोजन भी किया गया। इसमें केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. केएस भार्गव, डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. निशीथ गुप्ता, डॉ. लक्ष्मी, नीरजा पटेल, अंकिता पांडेय आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 महिलाओं ने भागीदारी की।

आदर्श गांव बनाने के लिए बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा

प्रसार वैज्ञानिक अंकिता पांडेय द्वारा वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक तरीके से फिनाइल बनाने का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें फिनाइल बनाने के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई, ताकि महिलाओं को कौशल विकास एवं स्वयं सहायता समूह के लिए सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर किया जा सके। प्रशिक्षण में टेरी से आई हुई अर्पिता ने बताया कि सिरोल्या गांव को आगामी दो वर्षों में आदर्श गांव की तरह विकसित किया जाएगा एवं आदर्श गांव बनाने के लिए बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, युवाओ में स्वरोजगार के लिए व्यवसाय, बिजली और, सड़क की व्यवस्था आदि पहलुओं पर काम किया जा रहा है।

पंचायत को नहीं मिल रहा काम, परिवार चलाने कर रहे मजदूरी

साक्षात्कार: जागत गांव हमार के सवालों का संतोष कलम ने बेबाकी से दिए जवाब

हरदा में सरपंच दिहाड़ी मजदूर!

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश की पंचायतों में अक्सर सुनने में आता है कि सरपंच ने मजदूरों का पैसा खा लिया। मजदूरों की जगह मशीन से काम कराया जा रहा है। लेकिन मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा की एक ग्राम पंचायत में पर्याप्त काम नहीं मिलने से सरपंच स्वयं मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। हम बात कर रहे हैं पेशे से मिस्त्री संतोष कलम की। जो जनपद पंचायत हरदा की रहटाखुर्द पंचायत के सरपंच हैं। जागत गांव हमार से खास बातचीत के मुख्य अंश...।

सवाल- रहटाखुर्द पंचायत में चुनाव हुआ था या निर्विरोध पंचायत है?

जवाब- हमारी पंचायत में चुनाव नहीं हुआ था। मैं निर्विरोध चुना गया हूं। यह आदिवासी सीट थी। दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था। जनता ने मुझे चुना। मप्र सरकार ने हमें निर्विरोध पंचायत का सात लाख भी दे दिए है। बारिश थमने के बाद उस फंड का भी इस्तेमाल विकास कार्य में किया जाएगा।

सवाल- अब तो आप लोगों का सरकार ने मानदेय तीन गुना बढ़ा दिया है?

जवाब- हां, यह सही बात है कि सरकार ने मप्र के सरपंचों का मान देय 1 हजार 750 रुपए से बढ़ाकर 4 हजार 250 रुपए महीना कर दिया है। उप सरपंच और पंच का 600 रुपए से बढ़ाकर अब 1800 रुपए महीना कर दिया है। लेकिन इतने में क्या परिवार चलाना संभव है। नहीं। इसलिए हमें काम करना पड़ता है।

सवाल- संतोष कलम जी! आप पहली बार सरपंच बने हैं? क्या कभी परिवार में कोई और सरपंच रह चुका है।

जवाब- मैं पहली बार सरपंच बना हूं। हां, मेरी बुआ स्व. अतर बाई 2005 से 2010 तक सरपंच रह चुकी हैं। मेरा पालन-पोषण बुआ ने ही किया है। जब मैं छोटा था तभी मेरे माता-पिता गुजर गए थे। तब से मेरी बुआ मेरे साथ ही रहती हैं। इस समय भी रहटाखुर्द पंचायत आदिवासी सीट थी। तब भी लोगों ने मेरी बुआ को सरपंच चुना था।

सवाल- सरपंच साहब! आप पढ़ाई कहां तक किए हैं। परिवार में शिक्षा का क्या स्तर है।

जवाब- मैं कक्षा छह तक पढ़ा हूं। परिवारिक स्थितियां ठीक नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे मेरी बुआ ने पाला है। रही परिवार की बात तो मेरे तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा 8वीं तक पढ़ा है। दूसरे नंबर का बेटा पढ़ाई नहीं कर पाया। तीसरा बेटा 10वीं पास है। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब उसको भी सोच रहा हूं। एक दुकान खोलवा दूं।

सवाल-आप सरपंच हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा क्यों?

जवाब- देखिए मैं सरपंच आज बना हूं। मैं 2009 से इस काम से जुड़ा हुआ हूं। सरपंच होने से कुछ नहीं होता। हमें पंचायत में इतना काम भी मिलना चाहिए। जो अभी मिल नहीं रहा है। हमें अपना परिवार भी पालना है। इसलिए जब पंचायत में काम नहीं होता है तो मैं काम करता हूं। पहले मैं सायकिल बनाता था। इसके बाद डीजे का साउंड सिस्टम भी बनाने लगा। जब धंधा चलना बंद हो गया तो मैंने कारीगरी सीख ली। अब लोगों के घर बनाने का काम करता हूं। यानी मैं मिस्त्री हूं। घर निर्माण से जुड़ा हर काम मुझे आता है।

सवाल-शासन से पंचायत के लिए जब कोई काम मिलता है तब क्या करते हैं?

जवाब- हमारी पंचायत के विकास के लिए जब कोई काम मिलता है तो मैं खुद ही कर लेता हूं। जैस-नाली निर्माण, नाडेप, सीसी रोड, सोक्ता गड्ढा और शौचालय में खुद ही बना लेता हूं। हमारे यहा सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यहां मजूदर भी नहीं मिलते हैं। यहां पटाखा फैक्ट्री खुलने से श्रमिकों की कमी हो गई है। पंचायत के अधिकांश लोग वहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं।

सवाल-आपको एक दिन में कितनी मजदूरी मिलती है, फिर उसका क्या करते हैं?

जवाब- देखिए, मैं जहां भी काम करता हूं, वहां ठेके पर करता हूं। कभी-कभी कहीं से फोन आ जाता है कि आज यहां बैठक है। कभी कलेक्टर या जिला जनपद सीईओ बैठक करते हैं तो सरपंचों को भी जाना पड़ता है। उस बैठक में मैं भी शामिल होता हूं। इसीलिए मैं ठेके पर काम करता हूं। ताकि बंधकर न रहूं। रही मजदूरी की बात तो आज हरदा में पक्का काम करने वाले मिस्त्री को 500 रुपए प्रतिदिन मिलता है और मजदूरों को 300 रुपए दिन के हिसाब से मिलता है। मुझे जो पैसा मिलता है तो उससे अपने परिवार का खर्च चलाता हूं।

सवाल-जब आप दूसरे जगह काम करते हैं तो पंचायत का काम भी प्रभावित होता होगा?

जवाब- नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता पंचायत है। लेकिन पंचायत में आज काम ही कहां मिल रहा है। सरपंचों को अगल से कोई फंड भी नहीं मिल रहा है। हम विकास के लिए प्रस्ताव दे देते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं प्रदान की जाती है। इसलिए देहाड़ी करना भी हमारी मजबूरी है। हां, जब पंचायत में काम होता है तो मैं खुद करता हूं या अपनी मौजूदगी में सारा काम कराता हूं। ताकि काम में कोई घपला न हो।

बीमारी का बढ़ा खतरा, वन्यजीव भी होंगे प्रभावित

ग्वालियर में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक मिली

प्रदेश के 10 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा अधिक

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के 10 जिलों के कई क्षेत्रों के भूजल में यूरेनियम नामक तत्व की मात्रा अधिक मिली है। इससे इस पानी का पेयजल के रूप में प्रयोग होने से लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। यूरेनियम की अधिक मात्रा वाला पानी पीने से लोगों में किडनी, लीवर खराब होने और कैंसर होने की आशंका बढ़ गई है। ग्वालियर के घाटीगांव क्षेत्र के भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक मिली है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारियों का यह भी कहना है कि भूजल में यूरेनियम की अधिक मात्रा होने पर वन्यजीव भी प्रभावित होंगे। अधिकारियों के अनुसार भूजल में यूरेनियम प्रदूषण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में गहन और व्यवस्थित अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है।

इतनी मात्रा सेहत के लिए घातक- पानी में 1.1 पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन मात्रा फ्लोराइड की पाए जाने पर वह मानव शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। इससे खास तौर पर बच्चों के दांत और हड्डियों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित हो रहे हैं।

इन जिलों के भूजल में मिला अधिक यूरेनियम

जिला	ब्लाक-गांव	यूरेनियम (प्रति लीटर में)
बालाघाट	कटंगी-कटेधरा	30.711
बैतूल	बैतूल	108.134
बैतूल	बैतूल-खेड़ी	39.402
छतरपुर	बिजावर-गुलगंज	47.453
छतरपुर	कुर्री	39.870
दतिया	भांडेर	32.870
दतिया	दतिया	96.716
दतिया	इमलिया	51.902
ग्वालियर	घाटीगांव	233.910
ग्वालियर	डबरा-टेकनपुर	58.497
झाबुआ	थांदला	75.001
पन्ना	शाहनगर-कौनखेड़ा	37.081
रायसेन	औबेदुल्लागंज-मेंडवा	51.323
सिवनी	केवलारी-धांगड़ा	203.303
सिवनी	कुरई-खवासा	61.394
शिवपुरी	पिछोर-डोला	79.072

(स्रोत: केंद्रीय भू-जल बोर्ड)

प्रदूषण नियंत्रण मंडल नहीं करता परीक्षण

हालांकि भारत मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए देश के राष्ट्रीय पेयजल मानकों में यूरेनियम शामिल नहीं है। राज्य का प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी भूजल में यूरेनियम की मात्रा का परीक्षण नहीं करता है। प्रदेश में पानी में फ्लोराइड की अधिकता वाले 15 जिले प्रदेश में पानी में फ्लोराइड की अधिकता वाले 15 जिले हैं। यहां राष्ट्रीय फ्लोराइड नियत्रंण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सरकार की हर साल होगी सात करोड़ की बचत

पहली सोलर सिटी सांची बचाएगी 2.3 लाख पेड़

भोपाल। जागत गांव हमार

विश्व धरोहर सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी होगी। सांची सोलर सिटी में की गई गतिविधियों से सालाना 13 लाख 747 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। यह लगभग 2 लाख 3 हजार वयस्क वृक्षों के बराबर है। आठ मेगावॉट की सांची सौर परियोजना में शासकीय एवं घरेलू भवनों पर 220 किलोवॉट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। शासकीय विद्यालय, जिला सहकारी बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, घर, कृषि सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। सौर ऊर्जा घरेलू, व्यावसायिक और कृषि विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

शासन और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर साल लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। ग्रिड कनेक्टेड सोलर संयंत्र से सांची शहर को 3 मेगावॉट और सांची ग्रामीण फीडर को 5 मेगावॉट बिजली दी जाएगी। शहर के नागरिकों को ऊर्जा के सदुपयोग एवं संरक्षण के प्रति व्यवहार में परिवर्तन के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान भी चलाया गया।

गोल्फ कॉर्ट की व्यवस्था

सांची स्तूप पर आवागमन के लिए गोल्फ कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जा रहा है। वाहनों के लिए ई-रिचार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। शहर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता एवं उपयोग के लिए विभिन्न ऑफग्रिड संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें सोलर वॉटर कियोस्क, सोलर स्टड, सोलर हाईमास्ट, सोलर ट्री, वर्टिकल एक्सिस, विण्ड टर्बाइन शामिल हैं।

सोलर लालटेन

शहर में घरेलू सौर उपकरणों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्कूली बच्चों को अध्ययन के लिए सोलर स्टडी लेम्प, छोटे व्यवसायियों के लिए सोलर स्टैंड लेम्प और बुजुर्गों एवं गृहणियों के दैनिक कार्यों के लिए सोलर लालटेन की व्यवस्था की गई है।

रूफटॉप सोलर क्षमता

सांची में रेलवे द्वारा 50 किलोवॉट, मध्यप्रदेश पर्यटन 104 किलोवॉट, स्कूल शिक्षा 13 किलोवॉट, पोस्ट-ऑफिस 3 किलोवॉट, पुरातत्व संग्रहालय 8 किलोवॉट, डिस्काम ऑफिस 2 किलोवॉट, सरकारी अस्पताल 10 किलोवॉट, घरेलू 45 किलोवॉट, इस तरह कुल 245 किलोवॉट की रूफटॉप सोलर क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करना जरूरी

संजय माकवे, वरिष्ठ पत्रकार

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। जलवायु परिवर्तन कोई एक देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है अपितु यह एक वैश्विक अवधारणा है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा, बीमारियां, प्रवासन आदि का खतरा बढ़ा है। लेकिन चूंकि भारत का एक बड़ा तबका (लगभग 60 प्रतिशत आबादी) आज भी कृषि पर निर्भर है। और इसके प्रभाव के प्रति सुभेद्य है इसलिए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कई दशकों में तापमान में वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण के प्रारंभ से अब तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के उच्च अक्षांश की और खिसकने से निम्न अक्षांश प्रदेशों में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत के जल स्रोत तथा भंडार तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे किसानों को परम्परागत सिंचाई के तरीके छोड़कर पानी की खपत कम करने वाले आधुनिक तरीके एवं फसल अपनानी होगी। ग्लेशियर के पिघलने से कई बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में दीर्घावधिक रूप से कमी आ सकती है जिससे कृषि एवं सिंचाई में जलाभाव से गुजरना पड़ सकता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रदूषण, भू-क्षरण और सूखा पड़ने से पृथ्वी के तीन चौथाई भूमि क्षेत्र की गुणवत्ता कम हो गई है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित दस शीर्ष देशों में शामिल है। जलवायु की बदलती परिस्थितियां कृषि को सबसे अधिक प्रभावित कर रहीं हैं, क्योंकि लम्बे समय में ये मौसमी कारक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व कृषि इस सदी में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार, वैश्विक कृषि पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। हालांकि कुछ फसल इससे लाभान्वित भी होंगी किन्तु फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक होगा। भारत में 2010-2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच उत्पादन के गिरने की संभावना है। एक शोध के अनुसार, यदि वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इससे गेहूं का उत्पादन 17 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसी प्रकार 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से धान का उत्पादन भी 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कई दशकों में तापमान में वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण के प्रारंभ से अब तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल के तापमान बढ़ने पर उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेंहू, सरसो, जौ और आलू आदि इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है जबकि तापमान का बढ़ना इनके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान आदि फसलों का क्षरण हो सकता है। क्योंकि अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता अथवा कम बनता है। इस प्रकार तापमान की वृद्धि इन फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

भारत का दो तिहाई कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और कृषि की उत्पादकता वर्षा एवं इसकी मात्रा पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा व तरीकों में परिवर्तन से मृदा क्षरण और मिट्टी की नमी पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि से वर्षा में कमी होती है जिससे मिट्टी में नमी समाप्त होती जाती है। इसके अतिरिक्त तापमान में कमी व वृद्धि होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है जिस कारण भूमि में अपक्षय और सूखे की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कुछ वर्षों से गहन रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मध्य भारत 2050 तक शीत वर्षा में 10 से 20 प्रतिशत तक कमी अनुभव करेगा। पश्चिमी अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र द्वारा सामान्य वर्षा की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करने की संभावना है। इसी प्रकार मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि एवं वर्षा में कमी से चाय की फसल में कमी हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों और रोगाणुओं में वृद्धि होती है। गर्म जलवायु में कीट-पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है जिससे कीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसका कृषि पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही कीटों और रोगाणुओं को नियंत्रित करने की कीटनाशकों का प्रयोग भी कहीं ना कहीं कृषि फसल के लिए नुकसानदायक ही होता है। यदि कुछ फसलों को छोड़ दिया जाए तो, कुल फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करनक के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देशों को अभी से नये उपाय करने होंगे। हमारी कृषि व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के अनेक उपाय हैं। जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण मैत्री तरीकों का प्रयोग करके कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किया जा सकता है।

प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है आक्रामक खरपतवार सियामः शोध निष्कर्ष

खरपतवार खेती को बर्बाद कर सकता है, इसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। अब शोधकर्ताओं ने बताया है कि, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में आक्रामक झाड़ी क्रोमोलाएना ओडोरेटा, जिसे सियाम खरपतवार के रूप में जाना जाता है, इसे प्राकृतिक तरीके से रोका जा सकता है। शोध में कहा गया है कि, इस खरपतवार के फैलने और रोकथाम के लिए सिटीजन साइंस एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन सीएबीआई की अगुवाई में किया गया है।

सीएबीआई के डॉ. मैथ्यू कॉक ने पारेउचैटेस स्यूडोइन्सुलाटा कीट की स्थापना और प्रसार का आकलन करने के लिए आईनेचुरलिस्ट.ऑर्ग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिसे सी. ओडोरटा को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के छह देशों में छोड़ा गया था। डॉ. कॉक ने ऑस्ट्रेलिया के कृषि और मत्स्य पालन विभाग और एमआईए कंसल्टिंग, यूटा, यू.एस. के सहयोगियों के साथ मिलकर मौजूदा जानकारी को एक साथ जोड़ा। पी. स्यूडोइंसुलता थाईलैंड और वियतनाम में स्थापित है जो चीन, कंबोडिया और पश्चिम मलेशिया तक फैल गया है। शोध के निष्कर्ष सीएबीआई एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। आईनेचुरलिस्ट पर सिविल साइंटिस्टों द्वारा साझा किए गए अवलोकनों से निकाले गए परिणाम भी दक्षिण भारत और श्रीलंका में पी. स्यूडोइन्सुलाटा की व्यापक स्थापना की पुष्टि करते हैं।

उनका तर्क है कि आईनेचुरलिस्ट जैविक नियंत्रण एजेंटों सहित, प्रचलित प्रजातियों की घटनाओं और इनके फैलने के बारे में जानकारी का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है, लेकिन यह सबसे प्रभावी होगा जहां विषयों को तस्वीरों से आसानी से पहचाना जा सकता है।

सिविल साइंटिस्टों को आम जनता की भागीदारी में किए गए वैज्ञानिक शोध के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कभी-कभी शौकिया या बिना-पेशेवर वैज्ञानिक भी कहा जाता है।

यूरोपीय आयोग की डिजिटल साइंस यूनिट और सोइनतीजे.ईयू द्वारा 2013 में प्रकाशित ग्रीन पेपर ऑन सिटीजन साइंस के अनुसार, प्रतिभागी शोधकर्ताओं के लिए प्रयोगात्मक आंकड़े और सुविधाएं प्रदान करते हैं, नए प्रश्न उठाते हैं और एक नई वैज्ञानिक संस्कृति का निर्माण करते हैं।

सी. ओडोराटा दक्षिणी अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना तक अमेरिका का मूल निवासी एक खरपतवार को खत्म करने वाली झाड़ी है, जो दुनिया के आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे खतरनाक आक्रामक पौधों में से एक बन गया है।

पी. स्यूडोइंसुलता अफ्रीका, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत के कुछ हिस्सों के चुने गए देशों में जारी किया गया था जो इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में स्थापित हो गया।

पी. स्यूडोइंसुलता के कई बार जारी करने, एजेंट द्वारा स्थापित नहीं किए जाने की जानकारी मिली थी जैसे थाईलैंड और वियतनाम, या यह आकलन करने के लिए कोई अनुवर्ती अध्ययन प्रकाशित नहीं किया गया है कि प्रयोग सफल थे या नहीं।

डॉ. कॉक ने कहा, यह शोध इनमें से कुछ रिपोर्टों की सच्चाई का पता लगाता है और खरपतवार जैविक नियंत्रण एजेंटों की स्थापना और प्रसार की निगरानी के लिए सिटीजन साइंस या नागरिक विज्ञान के उपयोग के अहमियत पर भी चर्चा करता है।

नागरिक वैज्ञानिकों द्वारा आईनेचुरलिस्ट पर साझा की गई छवियां कई क्षेत्रों में पी. स्यूडोइन्सुलाटा की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं, जिनमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां इसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी।

कई क्षेत्रों में इसे स्थापित करने की जानकारी दी गई है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए कोई तस्वीर नहीं थे, वे नागरिक विज्ञान परियोजना या जैविक नियंत्रण शोधकर्ताओं से जुड़े जमीनी सच के किसी अन्य रूप के बारे में बताते हैं।

अप्रत्याशित मानसून पैटर्न खेती के लिए संकट

भारतीय किसानों के लिए मानसून सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि बगैर मानसून के किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। यह लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है और विभिन्न क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करती है, जिसमें कृषि सबसे अधिक गहराई से प्रभावित होती है। भारी वर्षा और विशिष्ट मौसमी पैटर्न की विशेषता वाला मानसून का मौसम भारतीय कृषि की जीवनरेखा है। भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और स्थिति मानसून के लिए अनुकूल है। दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो जून के आसपास आता है और सितंबर तक रहता है, भारत में प्राप्त वार्षिक वर्षा का लगभग 70फीसदी के लिए जिम्मेदार है। यह मौसमी हवा पैटर्न मिट्टी की नमी को फिर से भरने, जलाशयों को भरने और फसलों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह सफल कृषि गतिविधियों के लिए एक आवश्यक कारण बन जाता है।

मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त और अच्छी तरह से वितरित वर्षा फसल की वृद्धि और उपज के लिए महत्वपूर्ण है। चावल, गन्ना, कपास और कई अन्य फसलें काफी हद तक मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं। सही समय पर पानी की उपलब्धता अंकुरण, स्वस्थ पौधों के विकास और मजबूत पैदावार को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत, अनियमित या अपर्याप्त मानसूनी वर्षा से जल संकट हो सकता है, जिससे फसल विकास प्रभावित हो सकता है और उपज में कमी हो सकती है। मानसून के मौसम के दौरान सूखे के कारण फसलें मुरझा सकती हैं, फलन कम हो सकता है और कुल मिलाकर उत्पादकता कम हो सकती है। भारत भर में किसान मानसून कैलेंडर के अनुसार अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाते हैं। मानसून की शुरुआत खरीफ सीज़न की शुरुआत का संकेत देती है, जिसके दौरान चावल, मक्का, बाजरा और दालों जैसी फसलों की खेती की जाती है। इस मौसम के दौरान पानी की प्रचुरता इन जल-गहन फसलों के विकास को प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर, रबी सीज़न, जो मानसून के बाद होता है। गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलों की खेती होती है, जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। विलंबित या कमजोर मानसून किसानों को अपनी फसल के विकल्प और रोपण कार्यक्रम में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रभावित हो सकती है।

अप्रत्याशित मानसून पैटर्न खेती की योजनाओं को बाधित कर सकता है, फसल की पैदावार को खतरे में डाल सकता है और किसानों की आय को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अल नीनो और ला नीना जैसी जलवायु संबंधी घटनाएं मानसून की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे कृषि उत्पादन में चिंता का कारण बन सकती हैं। कृषि पर मानसून परिवर्तनशीलता के प्रभाव को कम करने के लिए, कई तरह से प्रयास किया जा रहा है, जिनमें पर्यावरणीय प्रयासों से लेकर तकनीकी प्रयास तक किए जा रहे हैं। जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और जल-कुशल फसल प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय मानसून का कृषि पर गहरा प्रभाव जलवायु और खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध को रेखांकित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में, कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जलवायु परिवर्तन जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, नई चुनौतियों और अनिश्चितताएँ पेश करता है। टिकाऊ और लचीली कृषि प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए, किसानों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के बीच निरंतर अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। मानसून की क्षमता का दोहन करके और इसकी अनिश्चितताओं को अपनाकर, भारत कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है और अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

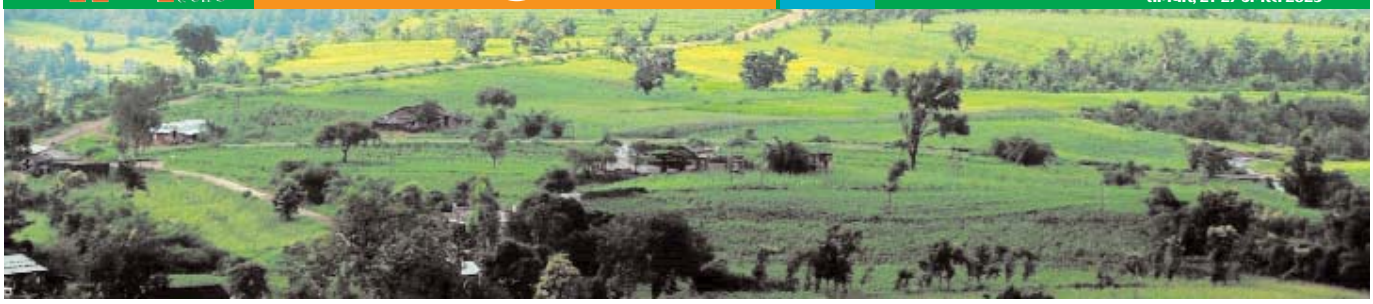

दो दशक में खरगोन जिले मे फसल उत्पादन और उद्योग के क्षेत्र में तेजी

कृषि विकास दर 3 से 17 फीसदी और उद्योग विकास दर 5 से 29 फीसदी

सिंचाई रकबा 145 फीसदी बढ़ने और खेती में लगातार नवाचार का असर

छह गुना बढ़ी कृषि औद्योगिक विकास दर और दस गुना हुई प्रति व्यक्ति आय

खरगोन। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश शासन की कृषि आधारित नीति के बल पर पिछले 20 वर्षों में खरगोन जिले में कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रगति की है। 94 फीसदी खेती के रकबे में सिंचाई और विभागीय योजनाओं के सहारे कृषि विकास की दर 3 से बढ़कर 17 प्रतिशत व कृषि आधारित उद्योग लगने से औद्योगिक विकास दर 5 से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2003 में 1 लाख 43 हजार 518 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अब रकबा 145 फीसदी बढ़कर 4 लाख 31 हजार 827 हेक्टेयर हो गया है। कृषि विभाग के मुताबिक किसान लगातार तकनीकी जैविक व प्राकृतिक फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से खरीफ, रबी और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में भी 50 से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। आगामी साल भर में 100 फीसदी रकबे में सिंचाई प्रस्तावित की गई है। वहीं जिले में महत्वपूर्ण उद्योगों की बात कि जाएं तो सनावद में 9.68 करोड़ रूपये की लागत से कुल कलस्टर की स्थापना की गई है। भूमि आवंटन भी शीघ्र होना है। जबकि बड़वाह में 6 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन किया गया। वहीं जिले में 350 से ज्यादा औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना 1500 करोड़ का पूंजी विनियोजन हो रहा है। शासन स्तर पर विकास पर्व मनाया गया। इस घड़ी में जिले की यह अभूतपूर्व उपलब्धि है।

मिर्च और कपास का निर्यात होना भी वजह

जिले में सालाना 500 क्विंटल मिर्च का निर्यात हो रहा है। 2003 में प्रदेश की बड़ी मिर्च बेडिया मंडी में 16481 क्विंटल मिर्च की आवक से 5 लाख 57 हजार 974 रुपए आय थी। अब आवक 4 लाख 2411 क्विंटल एवं आय 6 करोड 22 लाख 80 हजार 919 रुपए हो गई है। जबकि कपास का निर्यात 450 करोड़ के आसपास है। कॉटन यार्न, पीपी बैग्स, कार्टन बेल्स, फैब्रिक्स का अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विटजरलैंड, श्रीलंका, दुबई, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इटली तक जा रहा है।

20 साल में उत्पादन की स्थिति

वर्ष	खाद्यान्न	उद्यानिकी
2003	315380	164294
2023	1673543	946256
बढ़ोतरी	530 प्रतिशत	575 प्रतिशत

(उत्पादन के आंकड़े मेट्रिक टन में)

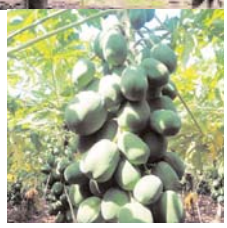

खरीफ उत्पादन की स्थिति

फसल	2003	2023
मक्का	38.524	319.728
कपास	192.220	412.874
गेहूं	92.405	875.593
चना	3.988	246.569

(आंकड़े हजार मेट्रिक टन में)

उद्यानिकी उत्पादन

फल	2003	2023
आम	1250	7128
अमरूद	2312	43250
केला	38080	237620
पपीता	4680	69929
नींबू	3300	16155
मिर्च	5150	73810

(आंकड़े मेट्रिक टन में)

नवाचार से बढ़ी कृषि व उद्योग की ग्रोथ

उप संचालक कृषि एमएल चौहान बताते हैं सिंचाई का रकबा बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। किसानों को फसल बीमा व समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ मिल रहा है। तकनीकी खेती के अलावा जैविक व प्राकृतिक खेती में लगातार नवाचार कर रहे हैं। उद्यानिकी अफसरों के मुताबिक उद्यानिकी फसलों में खाद्य प्रसंस्करण और मसाला सब्जियों में सीडलिंग को बढ़ावा देने से उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्नत खेती की रेड बेड, मलचिंग, अंतरवर्तीय खेती, शेड नेट हाउस, पाली हाउस, ड्रिप व स्प्रिंकलर आधारित खेती व योजनाओं का किसान अच्छी तरह से लाभ ले रहे है।

साल में चार बार उपज देने वाली खीरे की किस्म किसानों के लिए फायदेमंद

भोपाल। जागत गांव हमार

वर्तमान में किसान कम समय और कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाली फसलों की खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एसे में बाजार में पीसीयूएच किस्म का खास खीरा आया है। इसकी खेती साल भर में चार बार की जाती है। इस किस्म के खीरे की खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइये आपको इसकी खेती के तरीके के बारे में बताते हैं।

जलवायु व मिट्टी- यह खीरा रेतीली मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है। इस खीरे की खेती के लिए मिट्टी की पीएच 6 से 7 के बीच होनी चाहिए. इसकी खेती के लिए थोड़ा गर्म तापमान की जरुरत होती है।

खेत की तैयारी- खीरे की अच्छी पैदावार के लिए खेत को दो से तीन बार जोतने के बाद उसपर पाटा चला कर समतल कर देना चाहिए। इसमें आप देशी खाद का ही उपयोग करें और खेत में बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए अच्छी दवाइयों का छिड़काव करें।

खेती में सिंचाई

खीरे की फसल को अधिक नमी की जरूरत पड़ती है। गर्मी के दिनों में फसल को हर सप्ताह सिंचाई की जरुरत होती है। वर्षा ऋतु में आप बिना सिंचाई के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

निराई-गुड़ाई

खीरे के खेत से खरपतवार या अनावश्यक घास को हटाने के लिए खुरपी या फावड़े का उपयोग कर सकते है। ग्रीष्मकालीन समय में फसल में 20 से 25 दिनों के लिए 3 से 4 बार निराई-गुड़ाई कर देनी चाहिए। वहीं वर्षा के समय पानी की वजह से घास के जमने की आशंका ज्यादा हो जाती है। ऐसे में गुड़ाई की बारंबारता बढ़ जाती है।

धान की फसल को बैक्टेरियल ब्लाइट के प्रकोप से बचाने के उपाय

पूसा व्हॉट्सएप सलाह सेंग्मेंट कार्यक्रम के तहत विदिशा के किसान को दी सलाह

विदिशा। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाए गए पूसा व्हॉट्सएप सलाह सेंग्मेंट कार्यक्रम के तहत किसानों की समस्या का समाधान किया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा पूसा संस्थान किसानों से बात कर उनकी फसल व कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में जानती हैं तथा किसानों को उनके समाधान भी देती हैं। विदिशा मध्यप्रदेश के किसान अनिल मीणा जी ने ने पूसा संस्थान से धान में बैक्टेरियल ब्लाइट की समस्या बताई है। संस्थान ने कार्यक्रम के दौरान बैक्टेरियल ब्लाइट पर रोकथाम के उपाय इस प्रकार बताए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने जानकारी दी है कि अनिल मीणा की फसल में बैक्टेरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। जिसके समाधान के लिए किसान कॉपर आक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। सात दिन बाद स्ट्रेप्टोसाईक्लीन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें तथा 10-15 दिन बाद पुन: एक छिड़काव करें।

एक माह बाद बढ़े जलस्तर पर राजनेताओं में लगी श्रेय लेने की होड़

नहर में पानी बढ़ने से बच पाएगी मुरझा गई फसलें

श्योपुर। जागत गांव हमार

आखिरकार राजस्थान सरकार ने मप्र के किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए चंबल नहर में पानी की मात्रा दोगुनी कर दी है। नहर में पानी का प्रभाव अधिक होने से खेतों की अधिक सिंचाई हो सकेगी इसमें कोई दो राय नही हैं, लेकिन जिन खेतों में धान की फसल पानी के अभाव में पूरी तरह सूख गई है। क्या उन्हें एक माह बाद छोड़े गए इस पानी से सिंचाई कर बचाया जा सकेगा जबकि कई किसानों ने सिंचाई के अभाव में खराब हो चुकी फसलों को नई फसल लेने की आस में उलटना शुरू कर दिया है। उधर चंबल नहर में पानी बढ़ जाने का श्रेय सोशल मीडिया पर लेने में राजनेताओं में होड़ मच गई है।

अवर्षा से जूझ रहे किसानों ने चंबल नहर से पानी देने की मांग की थी इसके लिए कई ज्ञापन प्रदर्शन किसान संगठनों और राजनैतिक दलों ने दिए। सत्तापक्ष के नेताओं ने भी इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के मंत्रियों के माध्यम से नहर में पानी छोड़े जाने की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली थी। इसे मांगों का असर कहें या फिर अवर्षा की समस्या के राजस्थान सरकार ने समय से पहले चंबल नहर में पानी छोड़ने का काम कर दिया। नहर में पानी छोड़े जाने के बाद किसान संगठनों और नेताओं द्वारा लगातार पानी की मात्रा कम बताकर धरना ,प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। दिल्ली, भोपाल बैठे अपने नेताओं के माध्यम से भी नहर में पानी की सप्लाई बढ़ाने की मांग की गई। एक माह तक चले प्रदर्शन और मांग के बाद असर यह हुआ कि कोटा बैराज से राजस्थान सरकार ने चंबल नहर में पानी की मात्रा अधिक बढ़ा दी। जैसे ही पानी अधिक बढ़ने की सूचना मिली वैसे ही नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ भी मच गई। सोशल मीडिया पर नहर में पानी बढ़ाने को लेकर अपनी उपलब्धियों की बाढ़ सी आ गई।

केंद्रीय मंत्री और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दावे

चंबल नहर में पानी की मात्रा बढ़ने को लेकर राजनैतिक दल और नेताओं में होड़ सी मच गई ऐसे नेता मप्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्रीय मंत्री से भी चर्चा के फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हालांकि उनमें से किसके कहने पर नहर में पानी का बहाव बढ़ाया गया यह तो किसी को नही पता लेकिन चुनावी सीजन में नेताओं को लोकप्रियता पाने का यह मौका अच्छा मिला है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी एवं भारतीय किसान संघ ने नहर में पानी बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे थे। कांग्रेस नेता रामलखन हिरनीखेड़ा व अन्य ने किसानों के साथ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, विधायक बाबू जंडेल ने कोटा की कमिश्नर के साथ फोटो डालकर दावा किया कि उन्होंने नहर में पानी बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की। पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र जाट और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया के समर्थकों ने तोमर के साथ प्रतिनिधि मंडल का फोटो डाला।

इसलिए पड़ी नहर में पानी बढ़ाने की जरूरत

चंबल नहर में राजस्थान सरकार ने कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा था जिसकी मात्रा 1300 क्यूसेक बताई जा रही थी। जबकि चंबल नहर की पानी क्षमता 3000 क्यूसेक है, क्षमता से आधा पानी छोड़े जाने से समस्या यह हो गई कि हैडपोर्सन वाले किसानों को तो सिंचाई के लिए पानी मिल गया लेकिन टेलपोर्सन तक पानी पहुंचने में समस्या आ गई। कम पानी के चलते कई जगह किसानों ने माइनरी शाखाओं के गेट खोलने नही दिए और कई जगह जबरदस्ती गेट खोलने की नौबत भी आ गई। कम पानी के चलते किसानों में सिंचाई को लेकर आपसी संघर्ष की स्थिति भी निर्मित होने लगी। राजनैतिक दलों ने किसानों की इस समस्या का भरपूर राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया। कुछ किसान संगठन जो हमेशा किसानों की मांग के लिए संघर्षशील रहते हैं ने भी पानी बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए।

कई जगह उल्टी किसानों ने फसल

अवर्षा और क्रत्रिम संसाधनो से सिंचाई नही होने से कई खेतों में धान की फसल इस तरह सूख गई कि अब उसे बचाना मुश्किल है। किसान ऐसे खेतों में नई फसल रोपाई के लिए अवर्षा से बर्बाद हुई फसल पर ट्रेक्टर चलाकर उलटने का काम कर रहे हैं। कई किसानों ने अपने खेतों मे बर्बाद हुई फसल को खत्म करने के लिए मवेशी छोड़ दिए हैं, ऐसे किसानां को न तो सरकार की और से कोई मुआवजा मिलने वाला है और न ही फसल बीमा राशि का क्लेम, कुल मिलाकर अवर्षा किसानों के लिए काल साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को फसल का मुआवजा तब ही मिलता है जब सरकार क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दे।

उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए डॉ. राज सिंह कुशवाह

ग्वालियर। डॉ. राज सिंह कुशवाह प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र गवालियर को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 15 अगस्त को सम्मानित किया गया। डॉ. कुशवाह का कृषि की नई तकनीक को किसानों तक पहुचाने में अहम योगदान रहा।

श्रीमन शुक्ला ने मप्र मंडी बोर्ड के आयुक्त कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल। मंडी बोर्ड के नवागत आयुक्त सह प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला द्वारा कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करते ही श्रीमन शुक्ला द्वारा मंडी बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी उपस्थित अधिकारियों से ली जाकर अपनी प्राथमिकताओं को समस्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि आईटी के इस युग में मंडी बोर्ड को भी आईटी के क्षेत्र में अग्रणी रहना है। श्रीमन शुक्ला का स्वागत मंडी बोर्ड के निवर्तमान प्रबंध संचालक गौतम सिंह द्वारा किया गया। साथ ही अपर संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ डॉ. एसबी सिंह, आरआर अहिरवार, अधीक्षण यंत्री डीएस राठौर, संयुक्त संचालक संगीता ढ़ोके, उप संचालक रश्मि कश्यप, डॉ. पूजा सिंह, नितिन कोल्हे, चीफ प्रोग्रामर संदीप चौबे तथा मण्डी बोर्ड के समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वागत किया गया।

बोवनी कम होने से बाजार में बढ़ जाएंगी कीमतें

धान का रकबा 15 लाख हेक्टेयर बढ़ा दलहनी फसल के रकबे में आई कमी

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

कृषि मंत्रालय ने 18 अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों के बोवनी क्षेत्रों के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। वर्तमान में खरीफ सीजन की बोवनी लगभग पूरी हो गई हैं। इस हफ्ते खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की बोवनी का रकबा 15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। वही अगर दलहन फसलों की बात करें तो इस हफ्ते दलहन फसलों के रकबे में 9 फीसदी तक की कमी देखी गई हैं। इसके अलावा तिलहन फसलों, जूट व कपास की भी बोवनी घट गई हैं। हालांकि मोटे अनाज व गन्ने के बोवनी में क्षेत्र वृद्धि हुई हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अभी तक धान की 360.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे बुवाई की जा चुकी है। वही पिछले साल इस अवधि तक 345.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे धान बोई गई थी। तिलहन फसलों के रकबे में भले ही कमी आई हो लेकिन सोयाबीन की फसल के रकबे में 1 फीसदी वृद्धि हुई है। वर्तमान में सोयाबीन की 124.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की जा चुकी हैं। वहीं पिछले वर्ष इस अवधि तक 123.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन बोई गई थी। इसके अलावा मूंगफली की रकबा 44.48 लाख हेक्टेयर की तुलना में 42.77 लाख हेक्टेयर रहा हैं। ऐसे ही सूरजमुखी रकबा सिर्फ 66 हजार हेक्टेयर रहा है,जो पिछले वर्ष 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था।

खरीफ सीजन:सबसे चिंताजनक स्थिति दलहन फसलों की

खरीफ सीजन की फसलों सबसे चिंताजनक स्थिति दलहन फसलों की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दालों की बुवाई 114.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई हैं जबकि पिछले साल 126.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गई थी। उड़द की बोवनी 35.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में घटकर 30.19 लाख हेक्टेयर रह गई हैं। वही अरहर दाल की बोवनी 43.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में घटकर 40.92 लाख हेक्टेयर रह गई हैं। इसके अलावा मूंग के रकबे में भी कमी आई हैं। मूंग का रकबा घटकर 30.39 लाख हेक्टेयर रह गया जोकि पिछले साल 33.07 लाख हेक्टेयर था। दालों की बोवनी का इसी तरह रकबा घटने से उत्पादन प्रभावित होगा जिससे बाजार में इनकी कीमतें बढ़ेंगी।

छात्रों को बताया कैसे करें पपीता और मुनगा की बोवनी

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव जिला छतरपुर में कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) के लिए बीएससी कृषि फाइनल ईयर के 20 छात्र आए हैं। छात्रों को डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) के द्वारा पॉलीथिन पैकेट में पपीता एवं मुनगा के बीज की बुआई के तरीके बताए। किस प्रकार से करते ओर पॉलिथीन पैकेट भरने में क्या क्या सावधानियां रखते हैं। सम्पूर्ण विधियों को प्रायोगिक करवाकर छात्रों को विस्तार से बताया गया और प्रयोगिक करवाकर सिखाया भी गया। साथ ही पोधशाला में पौधों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए छात्रों को विस्तार से अवगत कराया गया।

पिछले 20 सालों में 11 बार औसत से कम रही जिले की बारिश

औसत से 40 फीसदी बारिश कम, पानी बिना सूख रही करोडो की धान की फसल

श्योपुर। जागत गांव हमार

जिले में पिछले एक पखवाड़े से बारिश का दौर थमा हुआ है। जिसके कारण खरीफ फसलें सूख रही हैं। विशेष कर करोडो रूपए कीमत की धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। कई किसानों ने सूख रही धान की फसल को उजाडना भी शुरू कर दिया है। ताकि रबी फसल की तैयारी कर सके। जिले में बीते ढाई माह के मानसून सीजन में अभी तक जो बारिश हुई है, उससे लगता है कि दो साल बाद फिर से जिला अल्पवर्षा की भेंट चढ़ेगा। क्योंकि अभी तक जिले में जो बारिश हुई है, वो औसत से 40 फीसदी कम है। विशेष बात यह है कि जिले के इतिहास के 20 सालों के इतिहास की बारिश देखें तो पाएंगे कि 11 बार औसत से कम बारिश हुई है।

822 मिमी है श्योपुर की औसत बारिश- भू अभिलेख द्वारा जिले में औसत बारिश 822 मिलीमीटर निर्धारित हैं। लेकिन इस बार 1 जून से 18 अगस्त तक की अवधि में 486.6 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है, जो कुल औसत बारिश का 59.19 फीसदी है। इस लिहाजा से अभी औसत का आंकड़ा 40 फीसदी से ज्यादा पीछे है। जबकि पिछले साल 1 जून से 18 अगस्त तक की अवधि में 589.7 मिमी औसत बारिश हो गई थी। जबकि इस समय बारिश का दौर थमा हुआ है,इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार जिले की बारिश औसत का आंकड़ा मुश्किल की छू पाएगी।

जिले में 20 साल में हुई औसत बारिश

वर्ष	बारिश मिमी में
2022	1295.78
2021	1495.0
2020	635.2
2019	948.0
2018	945.5
2017	406.4
2016	849.0
2015	545.0
2014	718.7
2013	1117.6
2012	865.1
2011	1035.8
2010	581.1
2009	512.7
2008	936.1
2007	443.7
2006	424.8
2005	708.4
2004	588.2
2003	716.0

जिले में अभी तक तहसीलवार बारिश

तहसील	बारिश (मिमी में)
श्योपुर	488.0
बड़ौदा	629.3
कराहल	540.7
विजयपुर	472.0
वीरपुर	303.0
कुल औसत	486.6

पानी बिना सूख रही फसल

बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलें सूख रही हैं। विशेषकर सबसे ज्यादा करोडो की पैदावार वाली धान की फसल प्रभावित हो रही है। हालांकि चंबल नहर में पानी आने से नहर के आसपास के क्षेत्र की धान की फसल में तो सिंचाई हो पा रही है, लेकिन टेल पोर्सन के खेतों में धान सूख गई है। क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि अब किसान ट्रैक्टर चलाकर धान की फसल उजाड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यही स्थिति रही तो आगामी दिनों और प्रतिकूल स्थिति बन सकती है।

डायग्नोस्टिक दल ने किया सोयाबीन और मक्का फसल का निरीक्षण, बताए उपाय

देवास। जागत गांव हमार

जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक दल द्वारा विकासखंड खातेगांव के ग्राम ओंकारा, सातल, सगोना, कालीबाई, पटरानी, निवारदी, मचवास, रतनपुर, गोपालपुर, हरणगांव, करोंदखुर्द आदि ग्रामों में सोयाबीन एवं मक्का फसल का निरीक्षण खेतों में जाकर किया। जिलास्तरीय डायग्नोस्टिक दल में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र देवास डॉ. मनीष कुमार, सहायक संचालक कृषि लोकेश गंगराड़े, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एनएस गुर्जर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केएस यादव शामिल थे।

भ्रमण के दौरान फसलों में कहीं-कहीं सफेद मक्खी, तम्बाकू की इल्ली, तना मक्खी, गर्डल बीटल इत्यादि कीटों का आंशिक प्रकोप पाया गया। साथ ही एन्थ्रेकनोज एवं येलो वेन मोजेक जैसे रोगों का प्रकोप भी देखा गया। दल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष कुमार ने पत्ती खाने एवं रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए थायोमिथोक्सम 12.60 प्रतिशत +लेम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 9.50 प्रतिशत, जेडसी 125 एमएल प्रति हेक्टेयर अथवा इंडोक्साकार्ब 15.8 ईसी 333 एमएल प्रति हेक्टेयर अथवा इमामेक्टिन बेन्जोएट 425 एमएल प्रति हेक्टेयर अथवा क्लोर एन्ट्रानिलिप्रोल 9.3 प्रतिशत+लेम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 4.60 प्रतिशत जेडसी 200 एमएल प्रति हेक्टेयर के छिड़काव की अनुशंसा की है। साथ ही फफूंद जनति रोगों के प्रकोप से सुरक्षा के लिए टेबूकोनाजोल 25.9 ईसी 625 मिली प्रति हेक्टेयर अथवा टेबूकोनाझोल 10 प्रतिशत+सल्फर 65 प्रतिशत डब्ल्यूजी 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा कार्बेंडाजिम+मेन्कोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अनुशंसित फफूंदनाशकों के छिड़काव की सलाह दी है। पौधों की रोग प्रतिरोध क्षमतावर्धन के लिए 0.0.50 (घुलनशील पोटाश) का 2.5 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना भी लाभदायक रहेगा।

सहायक संचालक कृषि श्री लोकेश गंगराड़े ने बताया कि कीटनाशक का छिड़काव करते समय पानी की पर्याप्त मात्रा का होना आवश्यक है। हस्तचलित स्प्रेयर पंप से यह मात्रा 450 लीटर प्रति हेक्टेयर एवं पॉवर स्प्रेयर से 350 लीटर प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है।

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन

रीवा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अर्न्तगत मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा द्वारा विध्य की पावन धरा के शहीदों को याद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन 9 से 15 अगस्त तक किया गया उक्त कार्यक्रम का आयोजन शहीद वीरों के नमन एवं संकल्प रीवा जिले के विभिन्न ग्रामों-मरैला माड़ौ नौडिया रीठी पड़िया आदि में उनकी समाधि स्थल पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने कृषकों के समक्ष गरिमामयी ढंग से किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ. एके पाण्डेय ने इस अवसर पर विंध्य के वीर शहीदों का स्मरण करते हुए उनकी संकल्प शक्ति एवं समर्पण को आत्मसात करने पर जोर दिया। विंध्य की पावन माटी व शहीदों के नमन कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों की सहभागिता रही। वीर शहीदों का सम्मान भी कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक और ऐलान

प्रदेश में मौजूद जनसेवा मित्र 4-5 पंचायतों के बीच एक की अभी है तैनाती

हर 50 परिवार पर तैनात होगा एक जन सेवा मित्र, जो करेगा इन परिवारों की चिंता

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेशभर में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की तादाद में बढ़ोतरी करने का एलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सीएम ने प्रदेश के हर 50 परिवार पर एक जनसेवा मित्र तैनात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करने वाले ये जनसेवा मित्र हर आम इंसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इन जनसेवा मित्रों से लोगों का फायदा पहुंचाने की यहां तक कोशिश है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से राशन लेने नहीं जा सकता है तो ये जनसेवा मित्र उन्हें घर-घर तक राशन पहुंचाने में भी मदद करेंगे।

संख्या जल्द होगी तीन लाख - मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रशासन और जनता के बीच एक नई सीढ़ी खड़ी कर दी है। जो पात्र हितग्राहियों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में मौजूद जनसेवा मित्र 4-5 पंचायतों के बीच एक की संख्या में हैं। लेकिन जल्दी ही इनकी तादाद इतनी कर दी जाएगी कि हर पचास परिवार पर एक जनसेवा मित्र काम कर सके। उन्होंने कहा कि ये इन परिवारों की देखरेख भी करेंगे और उनकी चिंता भी करेंगे।

मानदेय का फायदा भी होगा

सीएम ने स्पष्ट किया कि देखरेख या चिंता के मायने किसी परिवार के बीमार को स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने से लेकर लोगों को राशन दिलाने तक की जिम्मेदारी पूरी करना है। भविष्य में प्रदेश में इन जनसेवा मित्रों की संख्या 3 लाख से ज्यादा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन इससे जनता को सहायता पहुंचाने का सुकून युवाओं को मिलेगा। साथ प्रशासकीय कामों की समझ लेने के मौके के साथ हर माह मिलने वाले मानदेय का फायदा भी इन्हें होगा।

विकास की नई तहरीर लिखी

मुख्यमंत्रीने कहा कि प्रदेश में विकास की एक नई तहरीर लिखी गई है। लेकिन यह काम सरकार ने अकेले नहीं किया बल्कि इसमें जनभागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। कोविड जैसे विकट काल से लेकर स्वच्छता, जल संरक्षण,पौधारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसे कामों में भी जनभागीदारी से उच्च सफलता और मापदंड हमने हासिल किए हैं।

अभी कितने जनसेवा मित्र

अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई सीएम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दो चरणों में अब 9 हजार से अधिक जनसेवा मित्र नियुक्त किए जा चुके हैं। जो प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में नियुक्त किए गए 4695 जनसेवा मित्र अपने कार्यकाल के 6 माह पूरे कर चुके हैं। इनको शुरुआत में 8 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था, जो अब बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अगले चरण में इसी अगस्त माह को इतने ही जनसेवा मित्र और नियुक्त किए गए हैं। अब नए और पुराने जनसेवा मित्र मिलकर प्रदेशभर के गांव-गांव तक जनता और प्रशासन के बीच सेतु बनकर काम कर रहे हैं।

जनसेवा मित्रों की विकास यात्रा

गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले छह महीन से मैदान में काम करते हुए जनसेवा मित्रों ने 16 हजार से ज्यादा पंचायतों तक पहुंच स्थापित की है। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना के सर्वे के लिए करीब 21 लाख महिलाओं से संपर्क किया। जनसेवा मित्रों ने इन महिलाओं के ई केवाईसी अपडेट कराने में सहयोग प्रदान किया।

पशुधन क्षेत्र 7.67 प्रतिशत की उच्च मिश्रित सालाना वृद्धि

केंद्रीय पशुपालन-डेयरी सचिव अल्का ने बैठक में दिए निर्देश

पशुपालन-डेयरी की बकाया राशि को खर्च करें राज्य

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव अल्का उपाध्याय की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों और संबंधित निदेशकों के साथ एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई जिसमें विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को लेकर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के अपर सचिव, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिवों, मुख्य लेखा नियंत्रक, सलाहकार (सांख्यिकी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उपाध्याय ने बैठक में विशेषतौर पर इस बात का उल्लेख किया कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान (स्थिर मूल्यों पर) साल दर साल लगातार 7.67 प्रतिशत की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा कि यह डेयरी, गौवंश, कुक्कट पालन, बकरी/सुअर पालन जैसे पशुधन क्षेत्र के मानदंडों में स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 में समूचे कृषि और संबंधित क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में (स्थिर मूल्यों पर) 30.19 प्रतिशत के आसपास योगदान किया है।

वित्तीय प्रगति भी जानी

केन्द्रीय सचिव ने बैठक में भारत सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अमल में लाई जा रही सभी पशुपालन और डेयरी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास बकाया पड़ी राशि को खर्च करने पर जोर दिया। केन्द्रीय सचिव ने पुराने डेटा उन्नयन, भारतकोष के जरिये भुगतान पर ब्याज आदि से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के साथ करने पर भी जोर दिया ताकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोष जारी कर सके।

टीकाकरण पर फोकस

केंद्रीय सचिव ने देशभर में पशुओं में खुर पका-मुंह पका (एफएमडी) और ब्रुसेल्ला बीमारी से बचाव के टीकाकरण, चलती-फिरती पशु-चिकित्सा इकाई (एमवीयूएस), दूध और चारे की स्थिति आदि को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों के जरिये पशुधन की देखभाल और सुरक्षा भी विभाग के लिए गौर करने का विषय है।

जागरुकता अभियान चलाएं

केंद्रीय सचिव ने राज्यों को एफएमडी, ब्रुसेल्ला और पीपीआर टीकाकरण तेज करने की सलाह दी। उन्होंने पशुधन और डेयरी किसानों को योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से बताने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

पशु पालक परेशानः नौ हजार मवेशी संक्रमित

प्रदेश के पांच जिलों में लंपी वायरस का कहर

भोपाल। जागत गांव हमार

गौवंशी पशुओं में पाई जाने वाली लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) के प्रदेश के पांच जिलों में इस माह 39 मामले सामने आए हैं। इनमें 32 का संक्रमण अभी भी ठीक नहीं हुआ है। यह मामले प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीहोर और रीवा में हैं। बीमारी से बचाव के लिए अभी तक 45 लाख 83 हजार पशुओं को टीका लगाया गया है। यह बकरा-बकरी को गोटपाक्स बीमारी से बचाव के लिए लगता है जो लंपी में भी प्रभावी है। इस वर्ष अब तक इन्हीं पांच जिलों में नौ हजार 55 पशु संक्रमित हो चुके हैं, इनमें 41 यानी 0.45 प्रतिशत मवेशियों की मौत हुई है। इस वर्ष अभी तक सबसे ज्यादा 404 गांव बालाघाट में, इसके बाद 254 सिवनी, 29 रीवा, तीन सीहोर और

तीन छिंदवाड़ा में प्रभावित रहे। ये पांचों जिले पिछले वर्ष सितंबर के बाद लंपी के चपेट में आए थे। इसके बाद बीच में मामले कम हो गए थे। इस वर्ष मई के बाद फिर संक्रमण बढ़ा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)